

कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क,

बनाम

मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड

फरवरी 26, 2004

(एस. राजेंद्र बाबू, डॉ. एआर. लक्ष्मणन और जीपी माथुर, जेजे)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944-धारा 2(डी) और 3-केन्द्रीय उत्पाद टेरिफ अधिनियम 1985-स्टील शीट के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली जिंक ड्रास और फल्क्स स्किमिंग पर राजस्व द्वारा उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु मानते हुए उत्पाद शुल्क लगाना -माना गया, जिंक ड्रास व फल्क्स स्किमिंग एल्यूमिनियम शीट्स के निर्माण की प्रक्रिया में निकलने वाला कचरा मात्र है जो विपणन योग्य वस्तु नहीं है और इसलिए उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं है।

प्रत्यर्थी -निर्धारित स्टील शीट के निर्माण और स्टील शीट के गैल्वनीकरण में लगे हुए। गैल्वनीकरण की प्रक्रिया के दौरान दो उत्पाद जिंक ड्रास और फल्क्स स्किमिंग अस्तित्व में आते हैं। राजस्व ने पाया कि दोनो उत्पाद निर्धारित द्वारा केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944 के तहत बिना उत्पाद शुल्क अदा किये विक्रय किये गये हैं। राजस्व द्वारा निर्धारित को कारण बताओ नोटिस जारी कर विपणन योग्य वस्तु मानते हुए उत्पाद शुल्क व शास्ति की मांग की। कारण बताओ नोटिस के जवाब में निर्धारित

ने यह तर्क दिया कि उत्पाद विपणन योग्य वस्तु नहीं है और इसलिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 के तहत उत्पाद शुल्क लगाने योग्य नहीं है।

कलेक्टर ने निर्धारितियों की अपील खारिज कर दी और माल जप्त करने/माल के मोचन के आदेश दिये गये। अपील में सी ई जी ए टी ने कलेक्टर के आदेशों को अपास्त कर दिया।

इस न्यायालय में अपील के दौरान, राजस्व ने तर्क दिया कि जिंक ड्रास व फल्क्स स्किमिंग केन्द्रीय शुल्क उत्पाद अधिनियम 1944 के तहत "उत्पाद शुल्य योग्य वस्तु" है क्योंकि वे पहले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 79 के शीर्षक 79.02 के उपशीर्षक 7902.00 के अंतर्गत आते हैं तथा संशोधन के पश्चात शीर्षक 2660 के उपशीर्षक अध्याय 26 के अंतर्गत आते हैं।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि जिंक ड्रास व फल्क्स स्किमिंग स्टील शीट के गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में अपशिस्ट उत्पाद है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के तहत उत्पाद योग्य माल नहीं है।

अपीलो को खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा निर्धारित किया कि

अभीनिर्धारित: ड्रास व स्किमिंग एल्यूमिनियम शीट्स की निर्माण की प्रक्रिया में निकलने वाला कचरा, मैल या कचरा मात्र है और इसलिए इसे

उपचार, श्रम या हेर फेर का परिणाम नहीं कहा जा सकता है जिससे एक नया और अलग वस्तु एक विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग के साथ उभरती है जिसे आम तौर पर बाजार में लाया और बेचा जा सकता है। केवल इसलिए कि इस तरह के कचरे या मैल से बाजार में कुछ कीमत मिल सकती है, इसे उक्त उत्पाद कहा जाना उचित नहीं है, अंतिम उत्पाद या तैयार उत्पाद तो बिल्कुल भी नहीं। अपशिष्ट और फल्क्स स्किमिंग केवल विक्रय किये जाने के आधार पर ही विपणन योग्य वस्तु नहीं है। प्रत्येक वस्तु जो विक्रय की जाती है यह जरूरी नहीं है कि वह विपणन योग्य वस्तु हो व जिसका व्यापार करना सार्थक हो सकाता है। गैल्वनीकरण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले जिंक अपशिष्ट व स्किमिंग उत्पाद शुल्य योग्य वस्तु नहीं है। संदर्भित मामले

भारत संघ बनाम इण्डीयन एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (1995)

77 ई एल टी 268 सुप्रीम कोर्ट

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड बनाम सी सी ई, पटना

(2001) 135 ई एल टी 1142 (पैरा 7)

युनियन ऑफ इंडिया बनाम दिल्ली क्लोथ एण्ड जनरल मील कम्पनी

लिमिटेड ए आई आर 1963 एस सी 791

सेन्ट्रल एक्सार्इज कमिश्नर पटना बनाम इण्डीयन ट्यूब कम्पनी

लिमिटेड (1995) 77 ई एल टी 21 एस सी

काॅमरेड सी. एक्स. चण्डीगढ 1 बनाम मार्कफेड वनस्पति एवं संबद्ध इंडस, 2003 (153) ई एल टी 491 (एस सी) 2003(3) सुप्रीम 281, (पैरा 21)

भारत संघ बनाम अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लिमिटेड, 2003 (158) ई एल टी 3 (एस सी) 2003 (8) सुप्रीम 323, (पैरा 21)

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 524-526 वर्ष 1998, सिविल अपील संख्या 5664 वर्ष 2002 तथा 5262 वर्ष 2003

अपीलकर्ता की अेर से: ए.के. गांगूली, दिलीप टंडन, हेमन्त शर्मा और बी कृष्णा प्रसाद

प्रत्यर्थी की अेर से अधिवक्ता श्री जे वेलापल्ली, अजय अग्रवाल, सुश्री शिरीन खजूरिया, पुनित भारद्वाज, राजन नारायण, राजेश कुमार, आलोक यादव, वी लक्ष्मीकुमारन, राजेश कुमार

निर्णय न्यायमूर्ति डाॅ. ए.आर. लक्ष्मण द्वारा सुनाया गया-इन अपीलो मेें हम स्टील शीट्स के गैल्वनीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाले जिंक ड्रास और फल्क्स स्किमिंग पर उत्पाद शुल्क लगाने के सवाल से चिंतित है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य: स्टील शीट्स के गैल्वनीकरण के दौरान, जिंक ड्रास व फल्क्स स्किमिंग उत्पन्न होती है जिसे प्रत्यर्थी/ निर्धारित ने अपने ग्राहको की जानकारी के लिए मार्केटिंग डिविजन द्वारा प्रकाशित

अपने उत्पाद मैनुयल में उप उत्पाद के रूप में घोषित किया है। यह आरोप लगाया गया कि निर्धारित द्वारा वर्गीकरण सूची में कोई घोषणा किये बिना, उपरोक्त उत्पाद की निकासी पर कोई शुल्क चुकाये बिना और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों, 1944 के तहत निर्धारित किसी भी रिकार्ड को बनाये रखे बिना विभिन्न ग्राहकों को जिंक अपशिष्ट व फल्क्स स्किमिंग बेची जा रही है और उन्हें अपने डिस्पेच सलाह में गैर उत्पाद शुल्क योग्य के रूप में दिखाया गया है। विभाग के अनुसार, निर्धारितियों में शुल्क के भुगतान के साथ माल को मंजूरी दे दी है और इस प्रकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का उलंघन करते हुए शुल्क की चोरी की है और ऐसा करने में उन्होंने जिंक ड्रास और फल्क्स स्किमिंग के निर्माण के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लाईसेंस प्राप्त नहीं किया है जैसा कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 174 में आवश्यक है। इतना ही नहीं उन्होंने शुल्क के भुगतान से बचने के लिए उक्त माल के उत्पादन और निष्कासन को ही दबा दिया है।

विभाग के लिए मामला: निर्धारित को यह बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के प्रावधानों के तहत उन पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 9(2) के तहत शुल्क की मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए।

पार्टी के लिए मामला: कारण बताओ नोटिस के जवाब में निर्धारित ने लिखित बचाव में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के विभिन्न नियमों के उलंघन के सभी आरोपों से इन्कार किया है और कहा कि फल्क्स स्किमिंग सी ई जी ए टी द्वारा गैर उत्पाद शुल्क योग्य माना गया है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया है, और विशेष रूप से इंडियन एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम ए के बंधोपाध्याय [1980] 06 इ एल टी 146 (बोम्बे) के मामले में कहा गया कि ड्रास और स्किमिंग ना तो माल है और ना ही तैयार माल है जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के आईटम 25 के तहत शुल्क लगता है। जहां तक जिंक ड्रास का संबंध है, तो उन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इस वस्तु को गैर उत्पाद शुल्क योग्य घोषित करने का दावा किया है।

निर्धारित का यह तर्क है कि वह जिंक और उसके आर्टिकल का निर्माण नहीं करते हैं लेकिन वे अध्याय 72 के तहत आने वाली गैल्वेनाईज शीट का निर्माण करते हैं। चूंकि जिंक ड्रास व फल्क्स स्किमिंग को पहले से ही गैर उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु माना गया है, इसलिए गेट पास का मुद्दा उत्पादों को हटाने और त्रैमासिक रिटर्न आज ही जमा करने और वर्गीकरण सूची दाखिल करने की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। सभी निर्धारितियों ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के उलंघन से इन्कार किया है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने वर्गीकरण सूची प्रस्तुत की है और उनकी सद्भाविक

धारणा है कि माल गैर उत्पाद शुल्क योग्य है और उनके द्वारा निर्मित नहीं है, इसलिए किसी भी नियम के तहत जुर्माना लगाना असंभव है।

1998 की सिविल अपील संख्या 524 व 525 में, कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पटना ने जिंक ड्रास को जप्त करने का आदेश दिया। हालांकि कलेक्टर ने निर्माताओं को मोचन जुर्माने के भुगतान पर माल को छुड़ाने का विकल्प दिया। निर्माता पर जुर्माना भी लगाया गया। निर्धारितियों ने सी ई जी ए टी, नई दिल्ली में अपील की, जिसने भारत संघ बनाम इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (1995) 77 ई एल टी 268 सुप्रीम कोर्ट के मामले में दिये गये निर्णय पर भरोसा करते हुए कलेक्टर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आदेश को रद्द कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पटना ने उपरोक्त दो अपीले दायर की।

2003 की सिविल अपील संख्या 5262 में मैसर्स नेशनल स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जिसे अब मैसर्स नेशनल स्टील एण्ड एगो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ अधिनियम 1985 की अनुसूचि के शीर्षक 7902.00 के तहत जिंक ड्रास को वर्गीकृत करने की घोषणा दायर की। निर्धारितियों के अनुसार, उन्होंने जिंक के कचरे को गैर उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के रूप में दावा करते हुए घोषणा पत्र दायर किया और दिसम्बर 1997 तक शुल्क के भुगतान के बिना जिंक के अपशिस्ट को साफ करना जारी रखा। बाद में, उन्होंने विरोध

के तहत शुल्क का भुगतान किया। एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि जिंक अपशिष्ट को शीर्षक 7902.00 के तहत वर्गीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए और क्यों नहीं उत्पाद शुल्क वसूला जाना चाहिए। उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने माल को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1985 के शीर्ष 7902 के तहत वर्गीकृत किया और लगाये गये जुर्माने के भुगतान की पुष्टि की। आयुक्त (अपील) ने निर्धारित द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। अधिकरण ने निर्धारित की अपील पर इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के बाद अपील में दिये गये आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि जिंक ड्रास और फ्लक्स स्किमिंग उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु नहीं है। ट्रिब्यूनल ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड बनाम सी सी ई, पटना [2001 (135) ई एल टी 1142] और सिद्धार्थ ट्यूब्स लिमिटेड बनाम सी सी ई, इन्दौर दिनांक 08.04.2002 के मामले में दिये गये फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें फैसले का हवाला दिया गया था। ट्रिब्यूनल के समक्ष, विभाग द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि जिंक ड्राॅस एक विशिष्ट वाणिज्यिक वस्तु है और इस लिए उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी है।

2002 की सिविल अपील संख्या 5664 भी ऐसी ही परिस्थितियों से उत्पन्न हुई है। इस अपील में, निर्धारित के अनुसार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नमक अधिनियम, 1944 की धारा 2 (डी) में परिभाषित जिंक ड्राॅस और जिंक स्केलिंग उत्पाद शुल्क योग्य सामान नहीं है और इसलिए, उन्होंने

जिंक स्काॅलिंग पर भुगतान की गई शुल्क की राशि के लिए रिफंड दावे दायर किए।

विभाग के अनुसार, 01.03.1988 से पहले अध्याय 26 के अध्याय नोट 3 के अनुसार जिंक युक्त धातुओं या धातु यौगिकों के मैल और राख के अलावा अन्य राख और अवशेष केवल उद्योग धातुओं का निष्कर्षण या धातु के रासायनिक यौगिक के निर्माण के आधार के रूप में उपयोग की जाने वाली राख और अवशेषों पर लागू होते हैं। इस अध्याय नोट को बाद में 01.03.1988 से संशोधित किया गया था, जिसमें "धात्विक यौगिकों की धातुओं से युक्त जस्ता की गंदगी और राख के अलावा" शब्दों को हटा दिया गया था। इस प्रकार, 01.03.1988 से पहले उक्त धातु या धातु यौगिक युक्त जस्ता की गंदगी और राख 7902 के तहत वर्गीकृत की गई थी और 01.03.1988 के बाद उक्त उत्पाद को उप-शीर्ष 26.20 के तहत वर्गीकृत किया गया।

यहां भी एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और सहायक आयुक्त ने रिफंड दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि नोटिस प्राप्तकर्ता (निर्धारिती) द्वारा साफ की गई राख में धातु और जिंक ऑक्साइड शामिल हैं और इसका उपयोग धातु के निष्कर्षण के लिए आधार के रूप में भी किया जाता है। धातु के रासायनिक यौगिकों का निर्माण और वे विपणन योग्य हैं और अध्याय शीर्षक के विवरण का उत्तर भी देते हैं।

इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि इसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अध्याय शीर्षक संख्या 26.20 के तहत सही ढंग से वर्गीकृत किया गया है। आयुक्त के समक्ष निर्धारिती की अपील को भी खारिज कर दिया गया था और सीईजीएटी के समक्ष निर्धारिती द्वारा आगे की अपील की अनुमति दी गई थी। इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय का निर्णय। ट्रिब्यूनल ने, इस न्यायालय के फैसले का पालन करते हुए, स्पष्ट रूप से माना कि जिंक मैल और जिंक स्केलिंग माल नहीं हैं, इसलिए उत्पाद शुल्क योग्य नहीं हैं।

हमने प्रासंगिक रिकॉर्ड और नियमों यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों और संबंधित अधिकारियों और सीईजीएटी द्वारा पारित आदेशों का अध्ययन किया है और पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एके गांगुली और श्री जे. वेल्लापल्ली की दलीलें सुनी हैं। अन्य अपीलों में विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार और श्री आलोक यादव ने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्कों को अपनाया।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गांगुली ने प्रस्तुत किया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की उप-शीर्ष 7902.00 में जस्ता का अपशिष्ट और स्क्रेप शामिल है और जस्ता के अपशिष्ट और स्क्रेप में कचरा और राख शामिल है। श्री गांगुली के अनुसार, इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) का मामला एल्यूमीनियम ड्रॉस और

स्किमिंग से संबंधित है और एल्यूमीनियम अपशिष्ट और स्क्रेप की परिभाषा में ड्रॉस और स्किमिंग शामिल नहीं है और इसलिए, जिंक ड्रॉस और स्किमिंग को केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की शीर्षक संख्या 7902.00 के अंतर्गत कवर किया गया है। इसलिए वह प्रार्थना करते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा दायर अपीलों को अनुमति दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि 01.03.1988 से पहले, अध्याय 26 के अध्याय नोट 3 के अनुसार धातु या धातु यौगिकों वाले जिंक के मैल और राख के अलावा राख और अवशेष केवल उद्योग में धातुओं का निष्कर्षण या धातु के रासायनिक यौगिक के निर्माण के आधार के रूप में उपयोग की जाने वाली राख और अवशेषों पर लागू होते हैं। इस अध्याय नोट को बाद में 01.03.1988 से संशोधित किया गया था, जिसमें "धात्विक यौगिकों की धातुओं से युक्त जस्ता की गंदगी और राख के अलावा" शब्दों को हटा दिया गया था। इस प्रकार उनका कहना है कि 01.03.1988 से पहले, जस्ता युक्त धातु या धातु यौगिक की उक्त गंदगी और राख 7902 के तहत वर्गीकृत की गई थी और 01.03.1988 के बाद उक्त उत्पाद को उप-शीर्ष 26.20 के तहत वर्गीकृत किया गया। यह तर्क दिया गया कि उपरोक्त अध्याय नोट को बारीकी से पढ़ने से पता चलता है कि शीर्षक 26.20 में राख और अवशेष शामिल हैं जिनमें धातु या धातु यौगिक होते हैं और जो उद्योग में धातु या धातु यौगिक के निष्कर्षण के लिए या धातुओं के रासायनिक यौगिक के निर्माण के आधार के रूप में उपयोग किए जाते हैं।

तर्क का प्रतिकार करते हुए, प्रतयर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे. वेल्लापल्ली ने तर्क प्रस्तुत किया कि स्टील शीट के गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में जिंक ड्रॉस और फ्लक्स स्किमिंग अपशिष्ट उत्पाद थे और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत वस्तु नहीं हैं और वह गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में केवल पिघले हुए जस्ता के एक बैच के माध्यम से स्टील की चादरें शामिल होती हैं, जिससे उक्त चादरें सतह पर जस्ता की एक परत प्राप्त कर लेती हैं जिसके परिणामस्वरूप गैल्वनीकरण होता है और जस्ता का कचरा केवल अशुद्धता है जो गैल्वनीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है और नीचे जम जाता है। उसी गैल्वनीकरण प्रक्रिया के दौरान, अमोनियम क्लोराइड का उपयोग चादरों से अशुद्धियों को साफ करने के लिए फ्लक्स के रूप में किया जाता है। यह अमोनियम क्लोराइड जब पिघले हुए जस्ते के साथ मिलाया जाता है तो फ्लक्स के रूप में कुछ अशुद्धियाँ भी पैदा करता है जो सतह पर तैरने लगती हैं। यह फ्लक्स समय-समय पर जिंक की सतह से स्किम्ड होता है और इसे फ्लक्स स्किमिंग के रूप में जाना जाता है। विद्वान अधिवक्ता आगे यह भी कहेंगे कि जिंक मैल और फ्लक्स स्किमिंग और कुछ नहीं बल्कि बेकार उत्पाद हैं और ये विपणन योग्य नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता ने इंडियन एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने माना कि एल्युमीनियम ड्रॉस और स्किमिंग न तो माल हैं और न ही विपणन योग्य

वस्तु हैं और इसलिए, उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और इसलिए, वह, प्रार्थना करता है कि अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील खारिज कर दी जाए।

उपरोक्त दलीलों और तर्कों पर, इस न्यायालय के निर्धारण के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न उठ सकते हैं।

विचार के लिए जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या स्टील शीट के गैल्वनीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाली जिंक की गंदगी और फ्लक्स स्किमिंग केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत आने वाले माल हैं और राजस्व द्वारा वर्गीकृत केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी हैं।

या

क्या जिंक ड्रॉस और फ्लक्स स्किमिंग स्टील शीट के गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में अपशिष्ट उत्पाद हैं और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत माल नहीं हैं, जैसा कि निर्धारिती ने दावा किया है।

इस मामले में, उत्तरदाता स्टील शीट के निर्माण में लगे हुए हैं और स्टील शीट को गैल्वनाइजिंग भी कर रहे हैं। गैल्वनीकरण की प्रक्रिया के दौरान, जिंक मैल और फ्लक्स स्किमिंग अस्तित्व में आते हैं। निर्धारिती का तर्क यह है कि ये फ्लक्स और जिंक अपशिष्ट अपशिष्ट हैं और विपणन योग्य नहीं हैं। इंडियन एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि मैल और स्किमिंग न तो माल हैं और

न ही एन-उत्पाद। जैसा कि पहले देखा गया है, मैल और कुछ नहीं बल्कि धातुओं से किसी चीज में फेंका गया मैल है; कूड़ा-कचरा या बेकार अशुद्ध धातु और स्किमिंग वह है जो सतह से स्किमिंग द्वारा हटाया या प्राप्त किया जाता है। हमारी राय में, ये एल्युमीनियम सिल्लियों से एल्युमीनियम शीट के निर्माण की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली राख के अलावा और कुछ नहीं हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड [एआईआर 1963 एससी 791] में यह माना गया था कि "माल" कुछ ऐसा होना चाहिए जो आम तौर पर बाजार में आ सके और लाया और बेचा जा सके और "निर्माण" जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी है, इसलिए, "बाजार में ज्ञात एक नए पदार्थ को अस्तित्व में लाना" चाहिए।

परिच्छेद इस प्रकार है:-

"विनिर्माण" का तात्पर्य परिवर्तन से है, लेकिन प्रत्येक परिवर्तन निर्माण नहीं है और फिर भी किसी वस्तु का प्रत्येक परिवर्तन उपचार, श्रम और हेरफेर का परिणाम है। लेकिन कुछ और भी आवश्यक है और परिवर्तन होना ही चाहिए; एक विशिष्ट नाम, उपयोग की प्रकृति वाला एक नया और अलग आर्टिकल सामने आना चाहिए।"

हमारी राय है कि मैल और स्किमिंग एल्युमीनियम शीट के निर्माण की प्रक्रिया में निकलने वाला कचरा, मैल या कचरा मात्र है और इसलिए, इसे उपचार, श्रम या हेरफेर का परिणाम नहीं कहा जा सकता है जिससे एक नया और अलग वस्तु एक विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग के साथ उभरती है जिसे आम तौर पर बाजार में लाया और बेचा जा सकता है। केवल इसलिए कि इस तरह के कूड़े या मैल से बाजार में कुछ कीमत मिल सकती है, इसे उप-उत्पाद कहा जाना उचित नहीं है, अंतिम उत्पाद या तैयार उत्पाद तो बिल्कुल भी नहीं।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय ने इंडियन एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) में बरकरार रखा था। इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

"अपीलकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार करना भी संभव नहीं है कि एल्युमीनियम ड्रॉस और स्किमिंग्स एक "माल" या विपणन योग्य वस्तु है जिस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। निस्संदेह, एल्युमीनियम ड्रॉस और स्किमिंग्स निर्माण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये और कुछ नहीं बल्कि अपशिष्ट या कूड़ा-कचरा है जिसे निर्माण के दौरान फेंक दिया जाता है। "ड्रॉस" शब्द को द न्यू शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

मैल:

"कचरा...(1) पिघली हुई धातु की सतह पर बनने वाले मैल को पिघलाकर धातु से अलग की गई अशुद्धियाँ...(2) किसी भी चीज़ के साथ मिश्रित विदेशी पदार्थ...(3) विशेष रूप से अस्वीकार्य, बकवास, बेकार पदार्थ किसी मूल्यवान चीज़ से विपरीत या अलग किया गया।"

अमेरिकन सोसाइटी फॉर मेटल्स द्वारा निर्मित एएसएम मेटल्स रेफरेंस बुक (दूसरा संस्करण, 1983) "ड्राइस" को इस प्रकार परिभाषित करता है:

"पिघली हुई धातुओं की सतह पर बनने वाला मैल मुख्य रूप से ऑक्सीकरण के कारण होता है, लेकिन कभी-कभी सतह पर अशुद्धियों के बढ़ने के कारण होता है।"

मैकग्रा हिल डिक्शनरी ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग (1984 संस्करण) इसे इस प्रकार परिभाषित करता है:

"एक अशुद्धता, आमतौर पर एक ऑक्साइड, जो पिघली हुई धातु की सतह पर बनती है।"

मैल और स्किमिंग में धातु का कुछ छोटा प्रतिशत हो सकता है। लेकिन मैल और स्किमिंग्स अपशिष्ट या स्क्रेप के समान धातु नहीं हैं। इस तरह के मैल और गंदगी से कुछ धातु निकालना संभव हो सकता है। इसलिए, उन्हें बेचा जा सकता है। लेकिन यह उन्हें विपणन योग्य वस्तु

नहीं बनाता है। जैसा कि बंबई उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने बताया है, कूड़ा भी बेचा जा सकता है। हालाँकि, जो कुछ भी बेचा जाता है वह आवश्यक रूप से एक विपणन योग्य वस्तु नहीं है जैसा कि वाणिज्य के लिए जाना जाता है और जिसका व्यापार करना सार्थक हो सकता है। इसलिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश सही निष्कर्ष पर पहुंचे कि नियम 56 ए का प्रावधान लागू नहीं है क्योंकि एल्यूमीनियम ड्रॉस और स्किमिंग्स उत्पाद शुल्क योग्य माल नहीं हैं।

निर्धारितियों द्वारा बाहर से खरीदे गए कच्चे माल की पूरी मात्रा, अर्थात् शुल्क-भुगतान वाले एल्यूमीनियम सिल्लियों का उपयोग एल्यूमीनियम शीट के निर्माण में किया गया था। यह कोई मामला नहीं है कि मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निर्मित एल्यूमीनियम शीट वास्तव में उपयोग की तुलना में कम मात्रा में एल्यूमीनियम सिल्लियों से निर्मित की जा सकती थी। निर्माण की प्रक्रिया में, मैल और झाग को हटाना पड़ा ताकि अपेक्षित गुणवत्ता की एल्यूमीनियम शीट का निर्माण किया जा सके। इसका मतलब यह नहीं है कि एल्यूमीनियम सिल्लियों की पूरी मात्रा का उपयोग एल्यूमीनियम शीट के निर्माण के लिए नहीं किया गया था। निर्माण के दौरान, निर्माण की प्रक्रिया की प्रकृति के कारण कच्चे माल की एक निश्चित मात्रा नष्ट हो सकती है या कच्चे माल की कुछ छोटी मात्रा बर्बादी या राख का हिस्सा बन सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि तैयार उत्पाद शुल्क योग्य उत्पादों के निर्माण में पूरे कच्चे माल का उपयोग नहीं

किया गया था। खरीदे गए कच्चे माल की मात्रा और तैयार उत्पाद में पाए जाने वाले कच्चे माल के बीच एक सटीक गणितीय समीकरण संभव नहीं है, और इसकी तलाश नहीं की जानी चाहिए।

टैरिफ आइटम 27 के तहत "एल्यूमीनियम का अपशिष्ट और स्क्रेप" उत्पाद शुल्क के दायरे में आने वाली वस्तुओं में से एक है। वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा टैरिफ आइटम 27 में निम्नलिखित प्रभाव से एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया था:

"27. स्पष्टीकरण-(1) 'अपशिष्ट और स्क्रेप का अर्थ है अपशिष्ट और स्क्रेप धातु जो केवल धातु को पिघलाकर या रसायनों के निर्माण में उपयोग के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसमें कीचड़, मैल, स्केलिंग, स्कीमिंग, राख और अन्य अवशेष शामिल नहीं हैं।"

टैरिफ आइटम 68 जो पहली बार 1975 में पेश किया गया था वह इस प्रकार था:

"68. अन्य सभी सामान, जो कहीं और निर्दिष्ट नहीं हैं, लेकिन इन्हें छोड़कर-

(ए) *****

(बी) *****

(सी) *****

स्पष्टीकरण-इस मद के प्रयोजनों के लिए, जिन वस्तुओं को इस अनुसूची में किसी पूर्ववर्ती मद में संदर्भित किया गया है, ऐसे माल को उस मद में माल के विवरण से बाहर करने के उद्देश्य से (चाहे ऐसा बहिष्करण ऐसी मद के स्पष्टीकरण के माध्यम से हो या विवरण में या किसी अन्य तरीके से बहिष्करण के शब्दों द्वारा) उस वस्तु में निर्दिष्ट नहीं किया गया सामान माना जाएगा।

इन सभी अपीलों में प्रश्न आइटम 68 के कारण एल्युमीनियम मैल की अनिवार्यता और उत्पाद शुल्क में कटौती से संबंधित है और इसका स्पष्टीकरण आइटम 27 के स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाता है। अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आइटम 27 का स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि "एल्युमीनियम के अपशिष्ट और स्क्रेप" मद में मैल और झाग शामिल नहीं हैं। चूंकि इन्हें स्पष्ट रूप से आइटम 27 से बाहर रखा गया है, इसलिए इन्हें आइटम 68 में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि आइटम 68 का स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि जिन वस्तुओं को अनुसूची में किसी भी पूर्ववर्ती आइटम में संदर्भित किया गया है उन्हें वस्तुओं के विवरण से बाहर करने के उद्देश्य से उस मद को मद 68 में शामिल करना होगा।

पूरा तर्क इस आधार पर आगे बढ़ता है कि एल्युमीनियम ड्रॉस और स्किमिंग्स उत्पाद शुल्क योग्य सामान हैं। अन्यथा इन्हें टैरिफ मद 68 में

सम्मिलित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अपीलकर्ताओं ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि एल्यूमीनियम मैल और स्किमिंग्स बेचे जाने में सक्षम हैं। इसलिए इन्हें विपणन योग्य सामान माना जाना चाहिए। चूंकि वे निर्माण के दौरान उत्पन्न होते हैं, इसलिए ऐसे सामानों पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। तर्कों की बुनियाद इस धारणा पर टिकी है कि एल्यूमीनियम मैल और स्किमिंग्स विपणन योग्य सामान हैं। जिन कारणों के बारे में हम पहले बता चुके हैं, उनके लिए एल्यूमीनियम मैल और स्किमिंग्स को "माल" या वाणिज्यिक और विपणन योग्य वस्तु के रूप में मानना संभव नहीं है। कच्चे माल से अशुद्धियाँ निकालने की प्रक्रिया में, मैल और स्किमिंग्स विनिर्माण के दौरान दिया जाने वाला कचरा या राख मात्र हैं। यह कचरा अपशिष्ट और स्क्रेप से काफी अलग है जो अपने आप में प्रमुख धातु है।

आइटम 27 का स्पष्टीकरण "एल्यूमीनियम के अपशिष्ट और स्क्रेप" की मुख्य वस्तु से कुछ प्रकार के कचरे और स्क्रेप को अलग करने के उद्देश्य से नहीं है और इस प्रकार इसे आइटम 68 के तहत कर के दायरे में लाया जाता है। आइटम 27 का स्पष्टीकरण केवल कचरे को बाहर करता है और कुछ ऐसे अवशेषों या कूड़े-कचरे को हटा दें जिन्हें बिल्कुल भी "सामान" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। यह केवल वे सामान हैं, जो अन्यथा किसी दिए गए टैरिफ आइटम में शामिल होने के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से इससे बाहर रखा गया है, जो

अवशिष्ट टैरिफ आइटम 68 के अंतर्गत आते हैं। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा, जो कि सिविल अपील संख्या 1423/87 का विषय-वस्तु है, इस प्रकार के बहिष्करण के कई उदाहरण दिए गए हैं जो टैरिफ आइटम 68 के स्पष्टीकरण में शामिल हैं। इसमें एक मोटर का उदाहरण दिया गया है जो विशेष रूप से ग्रामोफोन में उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है या रिकॉर्ड प्लेयर जिसे स्पष्ट रूप से टैरिफ आइटम 30 से बाहर रखा गया है जो इलेक्ट्रिक मोटरों को कवर करता है। ये बहिष्कृत मोटरें भी मोटरें हैं, लेकिन उनके निर्माण में उन्हें प्रदान की गई कुछ विशिष्ट विशेषताओं के कारण, उन्हें टैरिफ आइटम 30 के तहत मूल्यांकन के लिए बाहर रखा गया है। इसी तरह, स्टील से बने स्लॉटेड एंगल और चैनल, जिनका उपयोग स्टील फर्नीचर के हिस्से के रूप में किया जा सकता है, हैं टैरिफ मद 40 से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है जिसमें स्टील फर्नीचर और हिस्से शामिल हैं। ये बहिष्करण इन उत्पाद शुल्क योग्य उत्पादों के सही मूल्यांकन के उद्देश्य से हैं। ये बहिष्कृत वस्तुएं अपने आप में "सामान" हैं, और बाज़ार में खुलेआम खरीदी और बेची जाती हैं। ऐसी बहिष्कृत वस्तुएं, यदि वे किसी अन्य वस्तु द्वारा कवर नहीं की जाती हैं, तो टैरिफ आइटम 68 के स्पष्टीकरण के आधार पर अवशिष्ट आइटम 68 में आ जाएंगी।

कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, पटना बनाम इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड [1995 (77) ईएलटी 21(एससी)] में, इस न्यायालय ने ट्रिब्यूनल

के तर्क को मंजूरी दे दी है कि पतला सल्फ्यूरिक एसिड, यानी तरल जो उपयोग के बाद में बच जाता है, यह नहीं कहा जा सकता कि यह एक निर्मित उत्पाद है और इसलिए शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं है और अपशिष्ट अचार शराब अपशिष्ट उत्पाद की प्रकृति में है और इसकी न तो विपणन क्षमता है और न ही बिक्री योग्यता है और इसलिए, शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं है।

कॉमरेड में.सी.एक्स., चंडीगढ़-। बनाम मार्कफेड वनस्पति एवं एलाइड इंडस का। [2003 (153) ईएलटी 491 (एससी)], इस मामले में विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या "खर्च की गई पृथ्वी" उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी है या नहीं। टैरिफ के तहत, 1985 में इसके संशोधन से पहले, यह लगातार माना जाता था कि "खर्च की गई पृथ्वी" शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालाँकि, 1985 में नए टैरिफ के लागू होने के साथ, ट्रिब्यूनल की विभिन्न पीठों के बीच टकराव पैदा हो गया। कुछ पीठों का मानना था कि "खर्च की गई पृथ्वी" अभी भी उत्पाद शुल्क योग्य नहीं है, जबकि अन्य पीठों का मानना था कि, क्योंकि अब यह एक विशिष्ट उप-शीर्षक में शामिल हो गया है, यह उत्पाद शुल्क योग्य हो गया है। इन परस्पर विरोधी निर्णयों के मद्देनजर, मामला सीईजीएटी की बड़ी पीठ के समक्ष रखा गया, जिसने माना कि "खर्च की गई पृथ्वी" अभी भी शुल्क योग्य नहीं है। इस न्यायालय के समक्ष दायर अपील में, इस न्यायालय ने यह साबित करने का भार रखा कि विनिर्माण होता है और जो निर्मित होता

है वह राजस्व पर होता है और केवल इसलिए कि कोई वस्तु टैरिफ प्रविष्टि में आती है, विनिर्माण नहीं माना जाना चाहिए। पैरा 6 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

"6. हालाँकि, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्राधिकरण में की गई टिप्पणियाँ "प्रति incuram" हैं। इस प्रकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, इंदौर बनाम यूनिवर्सल केबल लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ का निर्णय. [1995 सप्लीमेंट (2) एससीसी 465] में रिपोर्ट की गई, इस पर ध्यान नहीं दिया गया या विचार नहीं किया गया। इस मामले में एक तर्क कि एक वस्तु उत्पाद शुल्क योग्य हो जाती है क्योंकि यह टैरिफ एंट्री द्वारा कवर की जाती है, को नकार दिया गया है। बीपीएल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के मामले में। वी. केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर की रिपोर्ट में [1995 सप्लीमेंट (3) एससीसी 1] में यह भी माना गया है कि केवल इसलिए कि टैरिफ आइटम में बदलाव होता है, सामान उत्पाद शुल्क योग्य नहीं हो जाता है। इसके बाद 13 फरवरी, 2003 के एक फैसले में 1999 की सिविल अपील संख्या 6745 में यह माना गया है कि केवल इसलिए कि कोई वस्तु टैरिफ प्रविष्टि में आती है, यह तब तक उत्पाद शुल्क योग्य नहीं हो जाती जब तक

कि निर्माण न हो और माल विपणन योग्य न हो। लाल वूलन एंड सिल्क मिल्स मामले (सुप्रा) में ऐसा नहीं हुआ है यह माना गया कि विनिर्माण और विपणन योग्यता का दोहरा परीक्षण लागू नहीं होना चाहिए। इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि केवल इसलिए कि कोई वस्तु टैरिफ प्रविष्टि में आती है, यह माना जाना चाहिए कि उसका निर्माण हुआ है। कानून अभी भी यह बना हुआ है कि यह साबित करने का भार राजस्व पर है कि वहां विनिर्माण होता है और क्या निर्मित किया जाता है। इस मामले में, यह दिखाने के लिए कोई नया सबूत नहीं रखा गया है कि निर्माण हुआ है। "खर्च की गई पृथ्वी" "पृथ्वी" थी जिस पर शुल्क का भुगतान किया गया है। प्रसंस्करण के बाद भी यहमिट्टी ही बना रहता है। इस प्रकार यदि इस पर दोबारा शुल्क लगाया जाता है, तो यह उसी उत्पाद पर दोहरा शुल्क लगाने के समान होगा।"

भारत संघ बनाम अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड [2003 (158) ईएलटी 3 (एससी)] में, विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह उत्पाद शुल्क के लिए सिंडर की अनिवार्यता के संबंध में था। उक्त अपील में प्रत्यर्थी अंतिम उत्पाद के निर्माण के लिए अपने कारखानों में उपयोग की जाने वाली मशीनों को चलाने के लिए भाप का उत्पादन करने के लिए

ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करते हैं। भाप पैदा करने के लिए कोयले को बॉयलर या भट्टियों में जलाया जाता है। सामान्यतः कोयला जब बॉयलर में जलाया जाता है तो वह राख में बदल जाता है। कोयले का कुछ हिस्सा इसकी कम दहनशील गुणवत्ता के कारण पूरी तरह से नहीं जलता है। कोयले का यह अधजला या आधा जला हुआ कार्य बॉयलर में छोड़ दिया जाता है। इसे सिंडर कहा जाता है। इस निर्णय के पैरा 7 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए एक बिंदु प्रस्तुत किया गया था जिसे यहां नीचे उद्धृत किया गया है।

"7. क्या टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची की प्रविष्टियों में किसी वस्तु को शामिल करने से वह वस्तु उत्पाद शुल्क के योग्य हो जाती है?"

निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेदों को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी है जो निम्नानुसार हैं:

"हम विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3 पर बारीकी से नजर डालने से पता चलता है कि 'उत्पाद शुल्क योग्य सामान' शब्द को "जो भारत में उत्पादित या निर्मित किया जाता है" शब्दों द्वारा योग्य बनाया गया है। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि वस्तुओं का उल्लेख पहली अनुसूची की प्रविष्टियों में से एक में मिलता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं।

वस्तुओं को भारत में उत्पादित या निर्मित होने के परीक्षण को पूरा करना होगा। यह स्थापित कानून है कि उत्पाद शुल्क माल के निर्माण पर लगाया जाने वाला शुल्क है। जब तक माल भारत में निर्मित नहीं होता है, तब तक उन पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है। इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि केवल इसलिए कि किसी विशेष वस्तु का पहली अनुसूची में उल्लेख किया गया है, यह लागू हो जाता है उत्पाद शुल्क। [हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (1995) 5 एससीसी 338 और मोती लैमिनेट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, अहमदाबाद, (1995) 3 देखें। एससीसी 23]। इसलिए अधिकार और सिद्धांत दोनों पर, उत्पाद शुल्क के योग्य होने के लिए, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को भारत में उत्पादित या निर्मित होने के परीक्षण को पूरा करना होगा। इसके विपरीत तर्क खारिज किये जाते हैं।

हाल ही में इस न्यायालय को प्रयुक्त पृथ्वी पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के एक मामले से निपटने का अवसर मिला था। यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़ बनाम मार्कफेड वनस्पति एवं संबद्ध उद्योग मामले में था। 2003 (153) ईएलटी 491]। उत्पाद शुल्क का भुगतान "पृथ्वी" पर किया जा रहा था, 'खर्च की गई पृथ्वी वसायुक्त पदार्थों के उपचार के परिणामस्वरूप प्राप्त अवशेष है। खर्च की गई मिट्टी प्रसंस्करण के बाद भी मिट्टी ही बनी रही, हालांकि इसकी अवशोषित करने की क्षमता

कम हो गई थी। यह माना गया कि प्रयुक्त पृथ्वी पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इस मामले के तथ्य मौजूदा मामले के तथ्यों से काफी मिलते-जुलते हैं। मार्कफेड मामले में पृथ्वी को अवशोषित करने की कम क्षमता के साथ खर्च की गई पृथ्वी में तब्दील कर दिया गया था। मौजूदा मामले में, कोयले को निम्न गुणवत्ता वाले कोयले में बदल दिया गया था जो अब कारखानों में भट्टियों में उपयोग के लिए नहीं रह गया था, इसलिए, यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि सिंडर यानी कम गुणवत्ता वाला कोयला अभी भी कोयला था और उत्पाद शुल्क के दायरे में नहीं आता था।

मोदी रबर लिमिटेड, मोदी नगर, उत्तर प्रदेश एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य। [1987(29) ईएलटी 502 (डेल.)] में यह माना गया कि निर्माण की किसी प्रक्रिया से नहीं बल्कि अंतिम उत्पाद के निर्माण के दौरान प्राप्त अपशिष्ट/स्क्रेप उत्पाद शुल्क के दायरे में नहीं आता है। यह टायर, ट्यूब आदि के निर्माण का मामला था। अंतिम उत्पाद यानी टायर, ट्यूब, फ्लैप आदि का उत्पादन करने के लिए विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान अपशिष्ट को कटिंग के आकार में प्राप्त किया गया था। यह माना गया कि इस पर कर नहीं लगाया जा सकता, भले ही कचरे का कुछ बिक्री योग्य मूल्य हो। इसका मूल कारण यह था कि अपशिष्ट/कबाड़ के मामले में नई और अलग वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। विशिष्ट नाम, लक्षण और उपयोग वाला कोई नया पदार्थ नहीं लाया गया। विनिर्माण प्रक्रिया में

निर्माता द्वारा उपचार, श्रम या हेरफेर शामिल होता है जिसके परिणामस्वरूप एक नया और अलग आर्टिकल प्राप्त होता है। इसके लिए इनपुट या कच्चे माल के कुशल हेरफेर की आवश्यकता होती है, स्क्रेप के मामले में ऐसा नहीं था।

उल्लेखनीय है कि यूओआई एवं अन्य बनाम इंडियन एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड और अन्य। [1995 पूरक। (2) एससीसी 465] में यह माना गया कि निर्माण के दौरान फेंके गए अपशिष्ट या कूड़े को उत्पाद शुल्क के लिए योग्य विनिर्माण उत्पाद नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में मूल्यांकनकर्ताओं ने एल्युमीनियम सिल्लियों से एल्युमीनियम उत्पाद निर्मित किये। निर्माण की प्रक्रिया में धातु के ऑक्सीकरण के परिणामस्वरूप मैल और मलबा उठता है और राख के रूप में भट्टी में जमा हो जाता है। एल्युमीनियम के मैल में काफी मात्रा में धातु होती है जिससे वे आते हैं लेकिन उनमें न केवल धातु का शरीर होता है बल्कि धातु की ताकत, गठन और चरित्र की भी कमी होती है। इस तरह के मैल और स्किमिंग्स स्क्रेप से अलग होते हैं जो अच्छी गुणवत्ता की धातु है। निर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त मैल और स्किमिंग को प्रासंगिक समय पर उत्पाद शुल्क के दायरे में नहीं माना गया था। चूंकि मैल और स्किमिंग बाजार में बेचे गए थे, इसलिए यह तर्क दिया गया कि वे एक विपणन योग्य वस्तु थे और उन पर उत्पाद शुल्क लगाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये और कुछ नहीं बल्कि अपशिष्ट या कूड़ा-कचरा था जो निर्माण

के दौरान फेंक दिया जाता है। यह निर्णय खंडेलावल मेटल केस (1985) 3 एससीसी 620] पर आधारित अपीलकर्ता के विद्वान वकील के तर्क का भी जवाब देता है, जिसमें पीतल के सामान के निर्माण के दौरान उत्पादित पीतल स्क्रेप को उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी माना जाता था। वर्तमान मामले में, भले ही सिंडर कम कीमत पर बेचा जाता है, लेकिन इसे "विपणन योग्य" शब्द के अर्थ में एक विपणन योग्य वस्तु नहीं कहा जा सकता है। अत्यंत आवश्यकता के कारण सिंडर को उस स्थान से हटाना पड़ता है जहां यह होता है क्योंकि जब तक इसे नहीं हटाया जाएगा यह जमा होता रहेगा जिसके परिणामस्वरूप बहुमूल्य स्थान की हानि होगी। टिस्को के मामले में निचले अधिकारियों द्वारा नोट किए गए तथ्यों से पता चलता है कि टिस्को डंपिंग ग्रांड से सिंडर हटाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भुगतान कर रहा था। डंपिंग ग्रांड से, इसे उन पार्टियों द्वारा उठाया गया था जिन्हें इसे बेचा गया था। कथन के अनुसार, टिस्को सिंडर हटाने पर अपनी बिक्री से होने वाली आय से कई गुना अधिक खर्च कर रहा है। ये तथ्यात्मक मामले हैं जिन पर संबंधित अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है और इसलिए हमारे लिए इस सब पर विचार करने में बहुत देर हो चुकी है।

इन निर्णयों में निर्धारित परीक्षणों को लागू करते हुए, यह कहना संभव नहीं है कि सिंडर भारत में निर्मित होने की आवश्यकता को पूरा करता है।"

इस न्यायालय ने निष्कर्ष में कहा कि यह दिखाने का दायित्व राजस्व पर है कि जिस विशेष सामान पर उत्पाद शुल्क लगाया जाना है, वह भारत में निर्माण की प्रक्रिया से गुजरा है और राजस्व ने इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए कुछ नहीं किया है।

हमारी राय में, इंडियन एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय ने माना है कि केवल बेचने का मतलब यह नहीं है कि मैल और स्किमिंग विपणन योग्य वस्तुएं हैं क्योंकि यहां तक कि कचरा भी बेचा जा सकता है और हालांकि, जो कुछ भी बेचा जाता है, वह जरूरी नहीं है वाणिज्य के लिए ज्ञात विपणन योग्य वस्तु और जिसका व्यापार करना सार्थक हो सकता है। इस मामले में शामिल मुद्दा ट्रिब्यूनल और इस न्यायालय के पिछले निर्णयों द्वारा शासित होता है जहां ट्रिब्यूनल और इस न्यायालय ने माना था कि जस्ता का कचरा और स्किमिंग गैल्वनीकरण प्रक्रिया के दौरान अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न होने वाली वस्तुएँ उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएँ नहीं हैं। हमारी राय में, ट्रिब्यूनल ने इंडियन एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले पर सही भरोसा किया है और इंडियन एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय की राय के बाद ट्रिब्यूनल के उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलकर्ता से असहमत हैं कि जिंक ड्रॉस, फ्लक्स स्किमिंग और जिंक स्कैलिंग माल हैं और इसलिए उत्पाद शुल्क योग्य हैं।

राजस्व द्वारा दायर की गई अपीलों में कोई योग्यता नहीं है और वे खारिज किए जाने योग्य हैं और हम तदनुसार ऐसा करते हैं।

प्रतिवादी/निर्धारिती उनके द्वारा भुगतान किए गए शुल्क और जुर्माने, यदि कोई हो, की वापसी का हकदार होगा। कोई लागत नहीं

अपीलें खारिज

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनी वालिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)